

प्रेषक

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 18 सितम्बर अगस्त, 2012

विषय:—नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स के समान दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127% (एक सौ सत्ताईस प्रतिशत) एवं दिनांक 01.01.2012 से 139% (एक सौ उनतालिस प्रतिशत) की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-893/श0वि0नि0/031/पें0अके0-ii/2001 दिनांक 22 अगस्त, 2012 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पेंशनर्स को दिनांक 01.7.2011 से मंहगाई राहत की दर 127 प्रतिशत तथा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2— वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/XXVII(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी, 2012 द्वारा राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनर्स आदि को मंहगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127 प्रतिशत तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-155/XXVII(07)02/2012 दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से मंहगाई राहत 139 प्रतिशत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-155/XXVII(07)02/2012 दिनांक 13 जून, 2012 के पृष्ठांकन में यह उल्लेख किया गया है कि प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

3— अतः वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127 प्रतिशत (एक सौ सत्ताईस प्रतिशत) तथा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139 प्रतिशत (एक सौ उनतालिस प्रतिशत) स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है उन्हें पूर्व से राज्य सरकार के कर्मचारियों की भौति महँगाई भत्ता देय है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स की भौति नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मिकों को महँगाई राहत अनुमन्य होगी तथा जिन पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षित नहीं हुई है उन्हें पूर्व की दरों के आधार पर निर्गत शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगी।

4- उक्तानुसार दरों के संशोधन के फलस्वरूप धनराशि का वहन नगर निगम द्वारा स्वयं अपने वित्तीय स्रोतों से किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-155/xxvii (07)02/2012 दिनांक 13जून, 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या 833 /IV(1)/31.07.2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा०शहरी विकास मंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 7 उत्तराखण्ड देहरादून
9. वित्त (वे०आ०नि०स०)अनुभाग-7 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।